



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 31 मार्च, 1984/11 चंद्र, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा मुद्रण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 16 मार्च, 1984

संख्या 7-15/83-श्रम.—यतः इस विभाग की अधिसूचना संख्या 8-17/81 एल०ई०पी०, दिनांक 5-3-83 जो राजपत्र हिमाचल प्रदेश दिनांक 30-4-83 में प्रकाशित हुई थी, चाय बागान में काम कर रहे अध्रकुशल/कुशल कर्मचारियों/मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित करने हेतु आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे;

और यतः चाय बागान में काम कर रहे अध्रकुशल/कुशल कर्मचारियों/मजदूरों को मालिकों द्वारा दी गई अन्य सुविधाओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि चाय बागान में काम कर रहे अध्रकुशल/कुशल कर्मचारियों/मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी दर पुनः निर्धारित किये जायें;

और यतः उपरोक्त व्यवसाय में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1943 (1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और न्यूनतम वेतन समझौता बोर्ड के परामर्श पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बागान में काम कर रहे अध्रकुशल/कुशल कर्मचारियों/मजदूरों के दैनिक मजदूरी दर निम्नलिखित अनुसूची द्वारा नियत करने के प्रस्ताव को प्रकाशित करने के पुरस्कर्ता सहर्ष आदेश देते हैं :—

अनुसूची

किशोर.—किशोर मजदूरों की मजदूरी वयस्क मजदूरों के 90 प्रतिशत के बराबर होगी।

बाल श्रमिक.—बाल श्रमिकों की मजदूरी के वयस्क श्रमिकों की मजदूरी के 75 प्रतिशत होगी। तुड़ाई करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त निम्न प्रकार से प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा:—

ए-ग्रेड पत्तियां.—12 किलोग्राम से अधिक प्रति दिन पत्तियां तोड़ने वाले को 70 पैसे प्रति किलो की दर से प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।

बी-ग्रेड पत्तियां.—13 किलोग्राम से अधिक प्रतिदिन पत्तियां तोड़ने वाले को 55 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।

सी-ग्रेड पत्तियां.—14 किलोग्राम से अधिक प्रति दिन पत्तियां तोड़ने वाले को 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।

डी-ग्रेड पत्तियां.—16 किलोग्राम से अधिक प्रति दिन पत्तियां तोड़ने वाले को 35 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।

अंश कालिक श्रमिक को 70 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से मजदूरी दी जायेगी।

समस्त किशोर तथा बाल श्रमिकों को वयस्क श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत दिया जायेगा।

कारखानों तथा क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारी.—इस में अटारी मजदूर, पत्तियों को सुखाने वाले मजदूर, स्थानांतरित करने वाले मजदूर, खमीर उत्पादन करने वाले कमरे में काम करने वाले मजदूर, टी ब्वायज, सारटर, पैकर्स, टी-मेकर्स, टाइमकीपर तथा कैरियर (माली) समाविष्ट होंगे।

2. क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग में निम्नलिखित कर्मचारी समाविष्ट होंगे.—क्लीनर, सहायक क्लीनर, बागीचा सहायक, मोहरर आदि जो खेत के काम का रिकार्ड रखते हैं तथा इस में जमादार, माली तथा मेट भी शामिल होंगे।

दैनिक मजदूरी

वयस्क 8.40 रुपये

मासिक मजदूरी

252.00 रुपये

किशोर.—वयस्क मजदूरों की मजदूरी का 90 प्रतिशत दर से मजदूरी दी जायेगी।

1. अकाउंटेंट 567.00 रुपये मासिक

2. लिपिक 490.00 रुपये मासिक

3. मुन्शी 368.20 रुपये मासिक

4. चपड़ासी/ 261.80 रुपये मासिक

चौकीदार/

चोधरी।

स्वास्थ्य कर्मचारी वर्ग :

कम्पाउंडर 490 रुपये मासिक

राज्यपाल महोदय निम्नलिखित इलाकों में प्रत्येक के सामने दिखाई गई बढ़ौतरी के प्रस्ताव को भी प्रकाशित करते हैं :—

जगह का नाम

1. जिला लाहौल-स्पिति, किन्नौर, तहसील भरमौर तथा तहसील पांगी, जिला चम्बा

2. मलाना ग्राम पंचायत, जिला कुल्लू

3. डोडरा क्वार, तहसील रोहडू, जिला शिमला

4. चौहार बैली, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी

5. बड़ा भंगाल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा

बढ़ौतरी

25 प्रतिशत

जगह का नाम

बढ़ीतरी

1. तहसील रामपुर तथा चौपाल, जिला शिमला	} 20 प्रतिशत
2. तहसील आनी तथा निरमण्ड, जिला कुल्लू	
3. मांगल पंचायत, जिला सोलन	
4. चवासी इलाका, तहसील करसोग, जिला मण्डी	
5. गरवी देहात तथा बटवारी, तहसील मुन्दरनगर, जिला मण्डी	
6. छोटा भंगाल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा	
1. तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (डोडरा क्वार को छोड़ कर)	} 12½ प्रतिशत
2. सब-तहसील शिलाई, तहसील रेणुका, जिला सिरमौर	
3. तहसील चुराह, जिला चम्बा	
4. कुट पंचायत तथा परगना बेलज, जिला चम्बा	
5. इलाका मनाली तथा युहली पारवती तथा लाग वैली, बन्जार ब्लॉक, जिला कुल्लू	
6. झंजेहली ब्लॉक, तहसील चंचोट, जिला मण्डी	
7. तहसील करसोग, जिला मण्डी (चवासी इलाका को छोड़ कर)	

नोट.—1. उपरोक्त दर समस्त दरों को मिला कर होंगे।

2. महिला तथा पुरुष को समान मजदूरी दी जायेगी।

प्रभावी होने वाले व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव पर विचार इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तिथि के दो माह के पश्चात् किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित सभी आपत्तियां तथा सुझाव श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश को भेजे जाएं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 12 मार्च, 1984

संख्या पी0सी0एच-एच0ए(5)-62/82.—क्योंकि श्री केदार नाथ, प्रधान, ग्राम पंचायत गुम्बर हटली, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा नियमित जांच करने पर निम्नलिखित कृत्यों के लिए दोषी पाये गये हैं:—

1. दिनांक 29-11-79 से 30-3-82 तक मु0 1184 रु0 बाबत गृह कर राशि अपने पास अनाधिकृत रूप से रख कर पंचायत फण्ड का दुरुपयोग करना;
2. 1-4-79 से 31-5-82 तक अनाधिकृत रूप से अपने पास मु0 3,000 से 5,000 नकद शेष रख कर पंचायत फण्ड का अल्पकालीन दुरुपयोग करना;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री केदारनाथ को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताप्रा नाटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,

1968 की धारा 54 के अन्तर्गत प्रधान पद से निष्कासित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर-भीतर जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से इस कार्यालय को पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने पक्ष में कुछ कहना नहीं चाहते तथा एक-पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

शिमला-2, 15 मार्च, 1984

संख्या पी0सी0एच-एच0ए(5)-44/83.—क्योंकि श्री ब्रह्मदास (निबन्धित) प्रधान, ग्राम पंचायत कारगू-जागीर, विकास खण्ड नदौन, जिला हमीरपुर के विरुद्ध खण्ड विकास अधिकारी नदौन की रिपोर्ट दिनांक 6-8-82 अनुसार निम्नलिखित आरोप हैं:—

1. दिनांक 12-6-82 से सभा निधि म0 4937-69 रु0 को अनाधिकृत रूप से अपने पास रखा है;
2. जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर की रिपोर्ट दिनांक 2-4-83 अनुसार मु0 9258-07 पैसे की धन राशि अपने निजी प्रयोग में व्यय कर रखी है जिसका विस्तृत व्योरा उक्त अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 2-4-83 में दिया गया है (प्रति संलग्न है); और क्योंकि उक्त आरोपों में वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री ब्रह्मदास के विरुद्ध आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(डी) के अन्तर्गत जांच करने हेतु उप-मण्डलाधिकारी (ना0), हमीरपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। वे अपनी रिपोर्ट शीघ्र जिलाधीश चम्बा को प्रेषित कर देंगे।

हस्ताक्षरित/-

अवर सचिव।

कार्यालय जिलाधीश, जिला सिरमौर, नाहन

कार्यालय आदेश

नाहन, 12 मार्च, 1984

संख्या पी0एस-2-मिस-119/79-1139-45.—चूंकि श्री प्रेम पाल सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत लानाभलडा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों की पालना में अनाचार, अनियमितता तथा पद के दुरुपयोग करने का आरोप होने के कारण कार्यवाही आवश्यक समझी गई है;

चूंकि श्री प्रेम पाल सिंह को इस कार्यालय के इसी क्रमांक के रजिस्टर्ड नोटिस संख्या 4712-15 दिनांक 13-1-1983 द्वारा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि वे कारण बताएं कि क्यों न उनको ग्राम पंचायत प्रधान के पद से निबन्धित किया जाए;

चूंकि श्री प्रेम पाल सिंह ने उक्त कारण बताओ नोटिस का जो उत्तर दिया उस पर विचार करने पर वह सन्तोषजनक नहीं पाया गया व अब यह उचित समझा गया है कि उन्हें प्रधान ग्राम पंचायत के पद से निबन्धित किया जाए।

अतः मैं, राम निवासी बंसल, जिलाधीश, सिरमौर मण्डल, नाहन, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत प्राप्त है श्री प्रेम पाल सिंह इस आदेश-पत्र के जारी होने के दिनांक से ग्राम पंचायत के कितनी कार्य, कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे तथा वे पंचायत का समस्त चाज, रिकार्ड, धन राशि व अन्य सम्पत्ति यदि कोई उनके पास हो वह उप-प्रधान ग्राम पंचायत लानाभलटा का तुरन्त सौंपेंगे ।

आर० एन० बंसल,
जिलाधीश,
जिला सिरमौर, नाहन ।

स्थानीय स्वशासन विभाग,

अधिसूचना

शिमला-171002, 16 मार्च, 1984

सं० एल०एस०जी०वी (7)-3/75.—हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम, 1968 (1968 का 19वां अधिनियम) की धारा 255 और 273 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और उक्त अधिनियम की धारा 255 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत इस विभाग की सम संख्या अधिसूचना दिनांक 9-5-1983 द्वारा जो कि राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण), दिनांक 21-5-83 में पूर्व प्रकाशित किये गये थे, के उपरान्त राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एकाउंट कोड, 1975 में सहर्ष निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

AMENDMENT

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the H. P. Municipal Account Amendment Code, 1983.

(2) This shall come into force with immediate effect.

2. *Amendment of Rule 182 (4)(c).*—The existing rule 182(4)(c) of Himachal Pradesh Municipal Account Code, 1975 shall be substituted as under:—

“the daily allowance payable to the Presidents of first class municipalities shall not exceed the amount that would have been payable had such person been a Government servant of Grade-I (higher category) and in case of Presidents of 2nd class municipalities and members of all municipalities had such persons been a Government servant of Grade-I (Lower category)”.

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

परिवहन विभाग

अधिसूचनायें

शिमला-2, 15 फरवरी, 1984

संख्या 6-76/83-परिवहन.—मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 63 की उप-धारा (3-ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू व काश्मीर राज्य और दिल्ली, चण्डीगढ़ संघ राज्यों के बीच माल वाहन गाड़ियों के लिए परस्पर करार करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसका प्राल्प संलग्न है, तथा उक्त उप-धारा की अपेक्षानुसार इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के

लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन की अवधि बीत जाने के बाद उक्त करार प्रारूप पर विचार किया जाएगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति के पहले उक्त करार प्रारूप के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से जो भी आपत्ति या सुझाव, सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को प्राप्त होगा, उस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

आदेशानुसार,
हर्ष गुप्ता,
सचिव।

NORTH ZONE RECIPROCAL AGREEMENT

Draft Reciprocal agreement for public carriers between the States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal and Union territories of Delhi and Chandigarh.

This agreement made thisday of..... one thousand nine hundred and eighty-four between the Governor of Bihar of the one part, the Governor of Haryana of the second part, the Governor of Himachal Pradesh of the third part, the Governor of Punjab of the fourth part, the Governor of Rajasthan of the fifth part, the Governor of Uttar Pradesh of the sixth part, the Governor of West Bengal of the seventh part, the Governor of Jammu and Kashmir of the eighth part, the President of India for and on behalf of the Union territory of Chandigarh of the ninth part, the President of India for and on behalf of the Union territory of Delhi of the tenth part.

Whereas by an agreement dated the 24th September, 1981 between the parties of the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and tenth parts, the said parties entered into a reciprocal agreement with a view to encourage long distance inter State transport of goods by and between the said States on the terms and conditions contained in the said agreement.

And whereas, by mutual agreement, the parties hereto have agreed to modify the terms and conditions of the said agreement dated the 24th September, 1981 and it has been decided to enter into an agreement as herein contained in partial modification of the existing agreement.

It is now agreed by and between the above parties as follows:—

I. That this reciprocal agreement shall come into force on the 1st April, 1984 and shall remain valid upto the 31st March 1989. It may be renewed for such further period as may be mutually agreed to by all the signatories to this agreement. For reasons to be given in writing by any of the signatory States, this reciprocal agreement may be revoked on three months' notice. Such revocation shall, however, abridge and modify the operation of this agreement only in so far as it relates to withdrawing State subject to the condition that permits already issued under this agreement will continue to be valid till the expiry of those permits irrespective of withdrawal by the State or States from this agreement.

II. The total number of vehicles for which composite permits shall be issued shall not exceed 450 for each of the States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh and Delhi. The composite permits issued by the competent transport authority of each signatory State shall be valid on all National and State Highways chosen for operation. A list of the National and State Highways in each signatory State is appended hereto as Annexure VI. The competent transport authority shall also

issue to each of such permit holders an authorisation in the form annexed to this agreement (Annexure I) and such authorisation shall correspond to the period for which the advance payment has been received provided that the authorisation at one time shall not exceed period of one year. In case an authorisation is issued during the course of a year (financial year) it shall expire on 31st March of that year.

It shall, however, be open to any public carriers plying under such authorisation to deviate from the specified routes to the extent not exceeding 30 km on either side of the specified routes.

III. (i) Each applicant for a composite permit shall have to choose a minimum of three States *i. e.* the home State and any two other States out of the remaining nine for operation with effect from the date of this agreement.

(ii) If a composite permit holder chooses to exclude a contiguous State for operation through which his vehicle must have to pass to reach any other State chosen for operation within the scheme, the holder of the permit, shall have to pay full taxes to the "transit State".

(iii) A composite permit holder of a State shall be allowed to operate in any other State, separately covered under a bilateral agreement, but the same vehicle will not be allowed to be used both for the composite permit scheme as also the bilateral agreement scheme in the same State.

(iv) An option once exercised by a composite permit holder will not be allowed to be changed before a period of one year.

(v) Notwithstanding that a composite permit holder will not be allowed the option once exercised to be changed before a period of one year as per sub-clause (iv) above, the composite permit holder may, at his option, come up at any time during the course of the year for addition of State or States covered by the zone in his authorisation, provided he is agreeable to pay full taxes for the year. During the period of authorisation once granted, no deletion of State or States once opted shall be allowed.

IV. A public carrier operating under this agreement shall be free to operate without restriction of routes in the home State whereas while operating in any area outside the home State such a public carrier shall not pick up or set down goods between any two points lying wholly within the jurisdiction of the reciprocating States *i. e.* in such cases vehicles shall be prohibited from carrying any intra-State business.

V. A public carrier operating under this agreement shall be subject to the following limitations and restrictions:—

(1) No vehicle may be authorised under this agreement which—

- (a) is more than four years old on the date of making applications for grant of the authorisation and which is more than nine years old at any point of time;
- (b) does not carry the prescribed markings and distinguishing particulars and is not painted in the prescribed colour scheme as provided in the schedule annexed hereto (Annexure V); and
- (c) is not fitted with a body in conformity with the pattern as specified in the scheme annexed hereto (Annexure V).

(2) A public carrier plying under this agreement shall at all times carry a bill of lading in the form prescribed in the schedule annexed (Annexure III). Carriage of goods not in conformity with the declaration in the bill of lading shall be construed as infringement of the condition of the permit making the permit holder liable under Sec. 60 of the M.V. Act, 1939.

- (3) Such vehicles shall conform to and comply with all provisions of the M. V. Act, as well as the provisions of the Motor Vehicles Rules framed by the home State subject to such restrictions as may be imposed by the State Governments from time to time under the provisions of the M.V. Act, 1939.
- (4) A public carrier plying under this agreement shall be allowed to ply his vehicle on all National and State Highways in the signatory States chosen for operation. In particular in the case of vehicle in hilly areas of Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, West Bengal, etc., the operation will be subject to the load and other restrictions as may be imposed by the State Government concerned for any particular route/area. The (Home) State may make a suitable endorsement on the permit particularly in regard to the hilly State of Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttar Pradesh etc. as necessary, that the heavier vehicles will not be allowed in the hilly region of these States.
- (5) The certificate of fitness of such a vehicle shall be liable to be suspended or cancelled by the competent authority of the home State if it is found to be not in conformity with the provisions relating to fittings, colour and body specification as detailed in the schedule annexed hereto (Annexure V).
- (6) Such a vehicle shall at all times carry a valid authorisation in the form as detailed in the schedule annexed (Annexure-I) hereto granted under this agreement and issued under the signature and seal of the competent transport authority of the home State.
- (7) Any authorisation holder plying under this agreement shall file a quarterly return in regard to such a vehicle in the form prescribed as detailed in the schedule annexed (Annexure IV) hereto in quintuplicate to the Secretary of the State Transport Authority of the home State who, in turn, shall furnish copies thereof to the Secretaries, State Transport Authorities of the other signatory States.
- (8) Such a vehicle shall at all times carry—
 - (a) a valid certificate of fitness;
 - (b) a certificate of registration; and
 - (c) bill/bills of lading covering goods actually carried in the vehicle at the moment.

VI. A vehicle plying under authorisation issued under the special agreement may be stopped and inspected for the purpose of enforcement of the provisions of this agreement by an officer of the rank of Assistant Inspector of Motor Vehicles or Sub-Inspector of Police or any other officer whose rank is mutually agreed upon by the signatory States. Such an inspecting officer shall issue a check report in triplicate, one copy of which shall be served on the person-in-charge of vehicle, the second copy shall be sent to the competent transport authority of the home State and the third copy sent to the competent transport authority of the State concerned. The competent transport authority of the home State, on receipt of the copy of the check report, may take such actions as he may deem fit.

VII. (1) A composite permit holder plying under authorisation shall be liable to pay as under:—

- (a) Motor Vehicles Tax and the Goods Tax obtaining in the home State.
- (b) A sum of Rs. 500/- per annum in lieu of taxes mentioned in clause (a) above to Delhi in case it is chosen for operation and a sum of Rs. 1000/- per annum in lieu of taxes mentioned in clause (a) above to each of the remaining States of his option other than the home State.

This sum shall be paid in advance by a crossed bank draft on or before the 15th of March, every year (irrespective of the RLW and PLW of the vehicle). For this purpose, all the signatory States shall make suitable provisions in their taxation laws. Each signatory State shall designate

a competent authority for the purpose of receiving the amount mentioned above on behalf of other States which shall thereafter be transferred to the respective States. Such competent authority shall stamp and endorse the authorisation to that effect. Any vehicle plying under such an authorisation in the absence of such valid endorsement shall be deemed to be plying in contravention of the condition of the permit and shall be liable to suspension and cancellation of the permit under section 60 of the M.V. Act, 1939.

The sum mentioned above will not be inclusive of municipal levies such as octroi etc. and composite permit holder will be liable to pay them separately.

(2) Notwithstanding that the amount is required to be paid for the whole year in advance as per sub-clause (1) above, the owner of the vehicle may at his option, pay it in two equal instalments, the first on or before the 15th March every year for the period April—September, and the second instalment on or before the 15th September, (of the current financial year) for the period October—March and obtain endorsement of having paid this tax from the competent authority of the home State in certificate specified in Annexure II.

(3) A composite permit holder shall be required to pay a fee of Rs. 300/- per year per vehicle for grant of an authorisation irrespective of the number of States chosen for operation. This sum shall be paid in advance in full irrespective of whether authorisation is granted at the commencement of a financial year or after the commencement thereof by bank draft to the competent authority of the home State who will retain the amount.

(4) If the vehicle covered by the authorisation is kept under non-use for a period/periods during the validity of the authorisation refund of amount under sub-clause (1), (3) and (7) for that period/periods will be allowed.

(5) If the initial authorisation is granted at any time after the first quarter of the financial year, the tax shall be assessed on pro-rata basis for the remaining quarters of the financial year including the quarter in which the authorisation is granted. For the purpose, a quarter shall be taken as a unit and not months and days provided that this relief shall not be admissible for subsequent authorisation.

(6) If the vehicle covered by the authorisation is sought to be replaced by another suitable vehicle after prior permission of the authority which originally granted the permit, the registration mark of the replaced vehicle may be noted by the home State Transport Authority in the authorisation and the tax already paid shall be deemed to have been paid for the replaced vehicle for the period following the date on which the vehicle is replaced.

(7) If an operator does not pay his composite tax within the prescribed period, he shall be liable to pay, in addition to the composite tax of Rs. 1000/-, an additional sum of Rs. 100/- per month or part thereof for each of the States covered by the scheme in respect of which payment is delayed. The said amount shall be payable through crossed bank draft in the name of the designated authority of the State concerned and shall be sent to the State concerned as and when received. The operator would also be required to pay any other penalty for delay in payment of home State taxes that might be imposed by that State under its own rules.

VII-A. If a composite permit holder proposes to replace his vehicle by another vehicle, the latter vehicle shall be not more than four years old on the date of application for such replacement.

VIII. The competent authority of the home State shall receive the amount on behalf of the other State as the case may be in the form of crossed bank drafts. These drafts shall be made payable in the name of the designated authority of the State concerned and shall be sent by the home State to the State concerned as and when received along with a statement showing the

details of the vehicle number, bank draft number and date and amount, period for which paid etc.

IX. (A) For the implementation of this agreement, the State Transport Authority or Regional Transport Authority, as the case may be, of the home State, shall issue composite permits for the inter-State route or routes or areas, as the case may be, covered by this reciprocal agreement for any three or more of the signatory States, such a composite permit holder shall have the benefit of rule framed under Sec. 68(2) (hh) read with Sec. 63(1) of the M.V. Act, 1939, referred to in para below; and the competent authority shall furnish copies of these composite permits (Part B only) to other signatory States within 30 days of issue.

(B) Further, all the signatory States shall frame a suitable rule under Sec. 68(2) (hh) read with Sec. 63(1) to provide that the composite permits so granted by any of the signatory States other than the home State shall be valid without countersignatures in the areas or the home State and the Secretary of the State Transport Authority or the competent authority, as the case may be, of the home State shall issue an authorisation in the form prescribed in the schedule (Annexure-1).

(C) Such composite permits shall be valid in all the signatory States other than the home State as specified in the permit. A list of these Highways is annexed in the schedule hereto. The composite permits shall also be valid on such other National Highways and the State Highways as may be notified from time to time by the Union Government or the State Government concerned and which are endorsed on the permit.

X. In this agreement, the term "home State" means the State in the territory of which the composite permit under section 56 has been granted and authorisation therefor is issued under this agreement.

XI. For the purpose of this agreement, the term "year" shall be deemed to be a financial year.

XII. For the purpose of this agreement, each of the ten parties hereto shall be deemed to be a 'State'.

()
Secretary to Government of Bihar Transport
Department, Patna (FOR AND ON BEHALF OF
THE GOVERNOR OF BIHAR)

()
Secretary to Government of Rajasthan
Home Department, Jaipur (FOR AND
ON BEHALF OF THE GOVERNOR
OF RAJASTHAN)

()
Secretary to Government of Haryana Trans-
port Department, Chandigarh (FOR AND ON
BEHALF OF THE GOVERNOR OF HARYANA)

()
Secretary to Government of Uttar
Pradesh Transport Department, Lucknow
(FOR AND ON BEHALF OF THE
GOVERNOR OF UTTAR PRADESH)

()
Secretary to Government of Himachal Pradesh
Transport Department, Shimla (FOR AND ON
BEHALF OF THE GOVERNOR OF HIMACHAL
PRADESH)

()
Secretary to Government of West
Bengal Home (Transport) Department,
Calcutta (FOR AND ON BEHALF
OF THE GOVERNOR OF WEST
BENGAL)

()
Secretary to Government of Jammu and Kash-
mir Transport Department, Jammu (FOR AND
ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF JAMMU
AND KASHMIR)

()
Home Secretary Chandigarh Adminis-
tration, Chandigarh (FOR AND ON
BEHALF OF THE PRESIDENT OF
INDIA).

()
Secretary to Government of Punjab Transport
Department, Chandigarh (FOR AND ON BEHALF
OF THE GOVERNOR OF PUNJAB)

()
Special Secretary (Transport) Delhi
Administration, Delhi (FOR AND ON
BEHALF OF THE PRESIDENT OF
INDIA)

ANNEXURE I

AUTHORISATION UNDER SPECIAL RECIPROCAL AGREEMENT

(Valid in the States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh and Delhi).

1. Name in full No.
(Starting with surname and complete address of owner)
2. Registration mark
3. Engine No.
4. Chassis No.
5. Original Permit No.
6. Permit Issuing Authority
7. Make
8. Year of manufacture
9. RLW.
10. ULW.
11. Payload
12. Period of validity of the authorisation:

From

To

13. Valid for the States:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

(Seal of the competent authority).

(Signature of the competent authority).

ANNEXURE II

CERTIFICATE OF PAYMENT OF TAX UNDER SPECIAL RECIPROCAL AGREEMENT

Name of the State	Amount paid	Rate of annual tax		Period for which paid	Registration No. of the Vehicle
		Particulars of bank draft and date	Date of payment		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

(Signature and seal of the authority).

ABSTRACT OF CONDITIONS OF COMPOSITE PERMIT

1. This authorises the operation of the vehicle on the National and State Highways in the signatory States chosen for operation other than the home State. A list of National and State Highways is annexed hereto. The vehicle shall also be valid on such other National Highways and State Highways as may be notified from time to time by the Union Government or the State Government concerned and which are endorsed on the permit.

The vehicle shall also be authorised to deviate upto 30 km. on either side of the specified routes.

2. While operating in any area outside the home State such a public carrier shall not pick up or set down goods between any two points lying wholly within the jurisdiction of the reciprocating State *i. e.* in such cases vehicles shall be prohibited from carrying any intra-State business.

3. The vehicle shall be painted in chocolate colour with broad white borders and board showing the following inscription in white letters on black background shall be carried prominently above the 'Public Carrier' board :—

Inscription.—Permit under special reciprocal agreement

*Valid in Bihar, Haryana, Himachal Pradesh,

Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh,

West Bengal, Chandigarh and Delhi.

*States not applicable to be striked off.

The vehicle shall be provided with a seat across the full width of the vehicle behind the driver's seat providing for a spare driver to stretch himself and sleep.

4. The vehicle shall at all times carry the bill/bills of lading (in the manner directed by the S.T.A, home State) covering the goods in vehicle.

4-A. If a composite permit holder proposes to replace his vehicle by another, the latter vehicle shall be not more than four years old on the date of application for such replacement.

5. The vehicle shall conform and comply with all the provisions of the M. V. Act, 1939 as well as the provisions of the M. V. Rules framed by the home State subject to such restrictions as may be imposed by the State Government from time to time under the provisions of the M. V. Act, 1939.

6. The vehicle shall at all times carry the original permit documents and the authorisation issued under this agreement.

7. A composite permit holder plying under such an authorisation shall be liable to pay an annual tax of a sum of Rs. 500/- per vehicle to Delhi, a sum of Rs. 250/- per annum in lieu of taxes mentioned in clause (a) above to Chandigarh and Rs. 1000/- per vehicle to each of the States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal for which he has opted in addition to the Motor Vehicles Tax and Goods Tax, if any, of the home State. This will be irrespective of the RLW of the vehicle and shall be paid in advance on or before the 15th of March, every year.

The composite permit holder may, at his option, pay the above tax in two instalments, the first on or before the 15th March (every year) for the period April—September, and the second instalment on or before the 15th September (of the current financial year) for the period October—March.

8. (i) Each applicant for a composite permit shall have to choose minimum of three States i. e. the home State and any two other States out of the remaining nine, for operation with effect from the date of this agreement.

(ii) If a composite permit holder chooses to exclude a contiguous State for operation through which his vehicle must have to pass to reach any other State chosen for operation within the scheme, the holder of the permit shall have to pay full taxes to the 'transit State' unless otherwise excepted.

(iii) An option once exercised by a composite permit holder will not be allowed to be changed before a period of one year.

(iv) Notwithstanding that a composite permit holder will not be allowed the option once exercised to be changed before a period of one year as per condition 8(3) above, the composite permit holder may, at his option, come up at any time during the course of the year for addition of State or States covered by the zone in his authorisation, provided he is agreeable to pay full taxes for the year. During the period of authorisation once granted, no deletion of State or States once opted shall be allowed.

9. If an operator does not pay his composite tax within the prescribed period, he shall be liable to pay, in addition to the composite tax of Rs. 1000/-, an additional sum of Rs. 100/- per month or part thereof for each of the States covered by the scheme in respect of which payment is delayed. The said amount shall be payable through crossed bank draft in the name of the designated authority of the State concerned and shall be sent to the State concerned as and when

received. The operator would also be required to pay any other penalty for delay in payment of home State taxes that might be imposed by that State under its own rules.

10. If a composite permit holder fails to apply for renewal of authorisation for minimum number of States required to be chosen for operation under the agreement within a period of one month from the date of expiry of previous authorisation, his permit shall be liable to be cancelled.

ANNEXURE-III

BILL OF LADING

Name and address of the permit holder	Truck No.	Bill No. Date.
Name of the consignors		
Name of the consignee		
Destination		

No. of articles	Description of goods	Cut. B. Mds. Kg.	Freight charges paid Rs. P.	Freight charges to pay Rs. P.	Total Bill No. Date : Received Package..... from..... Truck No..... Signature.....
--------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------------------	--	--

(Signature of the carrier).

Signature of the consignor.

At carrier's risk.

At owner's risk.

Value of the goods Rs.....

Delivery at.....

Note.—The bill of lading will be in the proforma given above and will be in quadruplicate, the original (white) to be carried in the vehicle, the duplicate (light green) for the consignor, the triplicate (pink) for the consignee, and the fourth copy (cream yellow) for record of the permit holder.

ANNEXURE-IV

QUARTERLY REPORT

1. Name of the operator and address
2. Registration mark of vehicle
3. Composite permit No.

SUMMARY OF TRIPS MADE DURING THE QUARTER

Total distance covered in the State of—

Month	Bihar	Haryana	H.P.	J & K	Pun- jab	Rajas- than	U.P.	West Bengal	Chandi- garh	Delhi	Total distance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Signature of the permit holder.

Date.....

Note.—In remarks column, state reasons for low or high running in any particular State or States and any other points which caused low operations.

ANNEXURE-V

Specifications of the colour scheme and special markings to be carried on the vehicle and the construction of vehicles

1. The vehicles shall be painted in chocolate colour with broad white borders. The words 'NZ' in big letters will be inscribed on two sides of the vehicles within a circle.
2. A board with the following inscription with white letters on black background shall also be carried so as to be clearly visible above the "public carrier" board :

<p style="text-align: center;">Composite Permit</p> <p style="text-align: center;">under Special Reciprocal Agreement</p> <p>*Valid in Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajashan, U.P., West Bengal, Chandigarh and Delhi.</p>
--

3. The vehicle shall be provided, wherever feasible, with a seat across the full width of the vehicle behind the driver's seat providing facility for the spare driver to stretch himself and sleep.

~~*Strike off the name of the State not applicable.~~

Shimla-2, the 14th March, 1984

[In pursuance of clause (c) of Article 348 of Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the 'English text' of notification No. 6-25/77 (Parivahan), dated 14-3-84 for the general information of the public].

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 14 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exempt the vehicles No. MRE-9415 and MMF-1364 of the Nehru Science Centre, Dr. E. Moses Road, Worli, Bombay-400 018, from the payment of the token tax in Himachal Pradesh.

By order,
HARSH GUPTA,
Secretary (Transport).